डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 सितम्बर, 2020, डिस्पेच दिनांक 1 सितम्बर, 2020

| वर्ष 64 | अंक 07 | भोपाल | 1 सितम्बर, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत व पारदर्शी बनाएंगे : सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया

अन्य प्रांतों के सहकारिता क्षेत्र का अध्ययन कराकर बनाऐंगे पारदर्शी व्यवस्था

भोपाल। सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत तथा पारदर्शी बनाया जाएगा। सहकारिता क्षेत्र को पारदर्शी बनाने के लिये गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना आदि राज्यों के सहकारिता क्षेत्र के अध्ययन के लिये विशेषज्ञों की टीम भेजी जाएंगी। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया मंत्रालय में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों की

बैठक को संबोधित कर रहे थे।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्राथमिक सहकारी समितियों में पिछली सरकार के कार्यकाल में जो गड़बड़ियाँ हुई, उनको रोकने के लिये क्या पारदर्शी व्यवस्था हो सकती है, उस पर अध्ययन करने की जरूरत है। इसके लिये सहकारिता से जुड़े विशेषज्ञों का अध्ययन दल बनाकर महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड आदि राज्यों में भेजे जायेंगे, इन अध्ययन दलों द्वारा प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिये जो सुझाव दिये जायेंगे। उन पर अमल कर सहकारिता के सिस्टम को पारदर्शी बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिये आप लोग भी लिखित में सुझाव दें। इन सुझावों के आधार पर बेहतर प्लानिंग के साथ उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया...

(शेष पृष्ठ 2 पर)

पैक्स एवं विपणन सहकारी संस्थाओं को बहुसेवी एवं बहुउद्देशीय बनाने म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा एक-एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण

भोपाल। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां एवं विपणन सहकारी समितियॉ किसानों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। प्रदेश में इन समितियों द्वारा किसानों के लिए ऋण आवश्यकताओं, कृषि आदान आपूर्ति का कार्य एवं विपणन सेंवाओं का कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही किया जा रहा है। इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान, कृषि आदान अनुदान भी विगत 20 वर्षो से उपलब्ध कराये जाने के पश्चात भी इन प्राथमिक समितियों के व्यवसाय के आकार में ना तो आशातीत वृद्धि हुई है और न ही ये वित्तीय रूप से सक्षम हो पायी है।

वर्ष 2011 से पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने हेतु नाबार्ड के माध्यम से एक वृहत कार्यक्रम

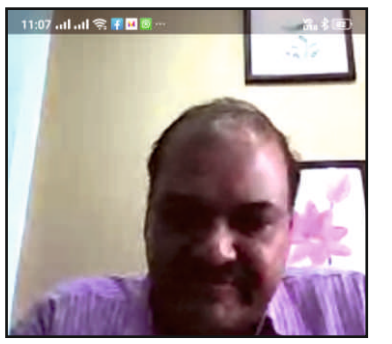

चलाया गया। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा पैक्स एवं विपणन समितियों को बहुसेवी एवं बहुउद्देशीय बनाने के लिए राशि रू. 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है जिसमें से रू. 7,444 करोड़ रू. म.प्र. के लिए आवंटित है। यह योजना पैक्स एवं विपणन समितियों के लिए एक अवसर है और इस अवसर के अंतर्गत केन्द्र सरकार की राशि नाबार्ड एवं एन.सी.डी.सी. के माध्यम से बहुत ही रियायती ब्याज दर पर पैक्स एवं विपणन समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है।

योजना के अंतर्गत निर्देश, मापदण्ड गतिविधियों की जानकारी, प्रोजेक्ट चयन हेतु सर्वे तथा डीपीआर का निर्माण आदि विषयों की जानकारी प्रदान करने हेतु म.प्र. राज्य सहकारी संघ के तत्वावधान में 11, 13 अगस्त व 14 अगस्त को ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। दिनांक 11 अगस्त को उज्जैन, इंदौर एवं नर्मदापुरम संभाग एवं 13 अगस्त को सागर, चम्बल, ग्वालियर, शहडोल संभाग और 14 अगस्त को रीवा, जबलपुर, भोपाल संभाग की सहकारी संस्थाओं/विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रदेश के प्रशिक्षण काल में यह पहला अवसर है जब माननीय सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव तथा आयुक्त सहकारिता श्री अशीष सक्सेना तथा नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती राजी गैन ने स्वयं उपस्थित रहकर प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया तथा उनसे फीडबेक भी लिया। प्रशिक्षण में प्रश्नोत्तर व खुली चर्चा भी शामिल किया गया था जिसका संचालन तथा प्रशिक्षण का संचालन राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा किया गया।

नाबार्ड के अधिकारी श्री मनीष गुप्ता ने पैक्स एवं विपणन समितियों को बहुसेवी बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र के रूप में अंतरित किये जाने हेतु भारत सरकार एवं नाबार्ड के दिशा निर्देश तथा श्री पी.के.एस. परिहार, से.नि. प्रबंधक, अपेक्स बैंक ने पैक्स एवं विपणन समितियों को बहुसेवी एवं बहुउद्देशीय के रूप में अंतरित करने हेतु प्रमुख गतिविधियों एवं उन गतिविधियों के चयन हेतु स्थानीय संसाधनों का सर्वे एवं सर्वे आधार पर प्रोजेक्ट का चयन, श्री अरविंद सिंह सेंगर, संयुक्त आयुक्त, सहकारिता ने सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स एवं विपणन समितियों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं ई प्लेटफार्म का महत्व पर तथा विषय विशेषज्ञ के रूप में एनसीडीसी के श्री आर.जी. मंगला ने चिंहित एवं चयनित गतिविधियों के आधार पर डीपीआर का निर्माण एवं अपेक्स बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/नाबार्ड/ एनसीडीसी को आवेदन दस्तावेज प्रेषण पर विस्तार से प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण को अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा ने भी संबोधित किया। यह अवसर निश्चय ही प्रदेश की सहकारिता के लिये मील का पत्थर साबित होगा लेकिन चुनौतियां भी है व्यवसायिक प्रबंध के साथ संचालन की अगर सफल रहे तो विकास गाथा सुनहरे अक्षरों से मील के पत्थरों पर लिखी जाएगी। हमे अपनी योग्यता से चुनौतियों का मुकाबला करते हुए सफलता की और कदम बढ़ाना होगा।

राज्य सहकारी संघ परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर प्रबंध संचालक श्री रंजन ने किया ध्वजारोहण

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ परिसर में श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में श्री संजय कुमार सिंह, राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी, श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, लेखाधिकारी, श्री गणेश मांझी, प्र. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केंन्द्र भोपाल, तथा अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक ने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों की करोना काल में आगामी प्रशिक्षण की चुनौतियां क्या है तथा इसमें हमें कैसे सफल होना है, संस्था के लिए लाभ कैसे अर्जित करना है, इस संबंध में समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। वर्तमान में चल रहें ऑनलाईन प्रशिक्षण पोर्टल निर्माण तथा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजनाओं में राज्य सहकारी संघ की मुख्य भूमिका योजना के लाभ का उल्लेख किया। साथ ही राज्य सहकारी संघ कें समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें दी।

पिछड़ी जनजातियों की पोषण सुरक्षा के लिए राज्य शासन प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

2 लाख 19 हजार बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से जारी किए 21 करोड़ 97 लाख रूपये

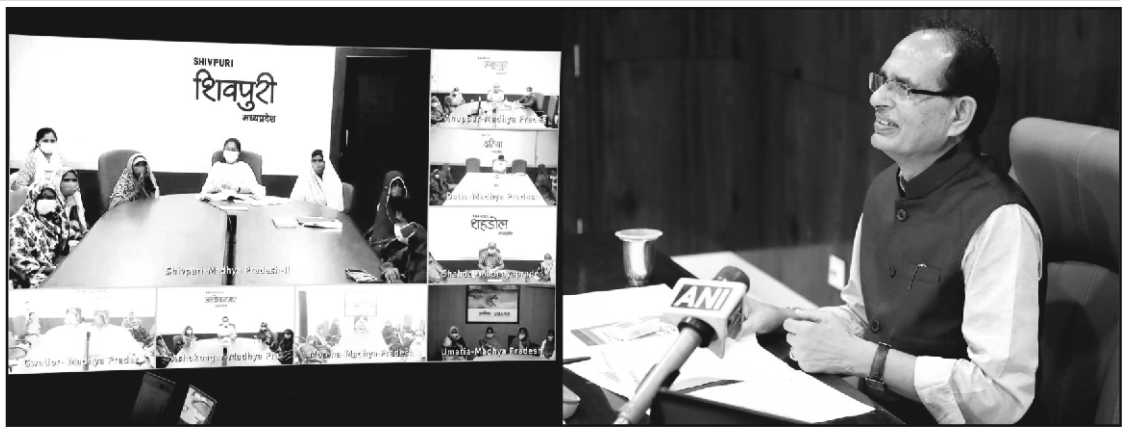

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैगा, भारिया और सहरिया जैसी दूरस्थ अंचलों में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं और बच्चों के उचित पोषण के लिये दी जाने वाली राशि का भुगतान समय पर किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय से आहार अनुदान योजना के तहत 2 लाख 19 हजार महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक से 21 करोड़ 97 लाख 80 हजार रूपए अंतरित कर भुगतान की नई व्यवस्था का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रतिमाह समय पर राशि का वितरण सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। इससे आगामी माहों के प्रारंभ में ही राशि हितग्राही के खाते में पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैगा, भारिया, सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों की पोषण सुरक्षा के लिए राज्य शासन प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आहार अनुदान योजना 2017 में आरंभ की गई थी, परंतु पिछले लगभग एक साल में हितग्राहियों को राशि नहीं मिल पाई। यह रूकी राशि 43 करोड़ रूपए आगामी सप्ताह में हितग्राहियों के खाते में पहुंच जाएंगी। पिछले ढाई वर्ष में 2 लाख 19 हजार से अधिक बहनों के खातों में 660 करोड़ रूपए पहुंचाए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश की विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया और सहरिया के परिवारों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए आहार अनुदान योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया के खाते में प्रतिमाह एक हजार रूपये की राशि भिजवाई जाती है। योजना में प्रदेश के 2 लाख से अधिक जनजाति परिवारों को लाभ मिल रहा है।

बैगाचक की भाजी का स्वाद याद आता है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आदिवासी महिलाओं से वी.सी. के माध्यम से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे आज भी बैगाचक की भाजी का स्वाद याद आता है। जब मैं वहां गया था तो मैंने एक बैगा बहन के हाथ की भाजी खाई थी। बैगाओं की संवदेनशीलता अद्भुत है, वे इसलिए हल नहीं चलाते कि पृथ्वी माँ के सीने में घाव नहीं हो जाए। भारिया जनजाति के साफ–स्वच्छ घर उन्हें आकर्षित करते हैं। सहरिया जनजाति शेर के साथ रहने वाली अत्यंत बहादुर जनजाति है।

बच्चों को पढ़ाओ, मामा साथ है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आदिवासी बहनें अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं। पढ़ाई की पूरी व्यवस्था उनका मामा करेगा। इसके साथ ही उनके रोटी, कपड़ा, मकान आदि की व्यवस्था भी सरकार कर रही है।

मैं आऊंगा तो रोटी खिलाओगी

मानपुर–मुरैना की आदिवासी बहन बैकुण्ठी से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने जब पूछा कि मैं जब तुम्हारे घर आऊंगा तो रोटी खिलाओगी, तब उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह बोली भैया जल्दी आना मैं खाना तैयार रखूंगी। शिवपुरी की रामकली देवी ने राशि मिलने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्री श्रीमती मीना सिंह से कहा ष्मंत्री मैडम धन्यवादष्।

जो छूट गई हैं उनके नाम जोड़ें

मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि विशेष पिछड़ी जाति की जो बहनें योजना में छूट गई हैं उनके नाम तुरंत जोड़ें। इसके साथ ही जिनके पास आवास नहीं है, उस संबंध में भी कार्रवाई की जाए।

हमारे भैया आ गए तो कैसी चिंता

अशोकनगर की पौनाबाई से जब मुख्यमंत्री ने पूछा कि उन्हें किसी बात की चिंता तो नहीं है, इस पर उन्होंने कहा कि उनके भैया आ गए हैं तो उन्हें कैसी चिंता। आप चले गए थे तो हमारे पैसे आना बंद हो गए थे। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि अब सभी को समय से पैसे मिल जाएंगे।

अब चूल्हे के लिए लकड़ी लेने जंगल नहीं जाना पड़ता

उमरिया जिले की नानबाई बैगा ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें योजना के पैसे तो मिल ही गए साथ ही नियमित रूप से राशन भी मिल रहा है। गैस मिल जाने से अब उन्हें चूल्हा नहीं फूंकना पड़ता और लकड़ी लेने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ता।

"जब तक जीना, तब तक सीखना"। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं।
– स्वामी विवेकानंद

योजना के प्रमुख बिन्दु

- प्रदेश की विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए आहार अनुदान योजना लागू है।
- विशिष्ट पिछड़ी जनजाति में शामिल हैं बैगा, भारिया और सहरिया।
- योजना के तहत प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रूपए का भुगतान हो रहा है।
- प्रदेश के 2 लाख 19 हजार हितग्राहियों को मिल रहा है योजना का लाभ ।
- 21 करोड़ 97 लाख 80 हजार रूपये सिंगल क्लिक से ट्रांसफर।
- बैगा– मंडला, शहडोल, डिंडोरी में, भारिया– छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, सतना, पन्ना और मंडला में तथा सहरिया– ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में प्रमुखता से निवासरत हैं।
- प्रदेश में निवासरत 43 जनजातियों में से बैगा, भारिया, सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं।

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत.....

जायेगा ताकि सहकारिता के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि निमाड़ क्षेत्र के लिये दुग्ध संघ बनाने का सुझाव प्राप्त हुआ है, इस संबंध में विभाग के आयुक्त व दूसरे अधिकारियों से चर्चा करेंगे तथा परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जाएगा।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' की दिशा में प्रदेश के विकास के लिये हर स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को गति देने तथा आम लोगों के हित में सहकारिता पर आधारित प्रोजेक्ट/प्रस्ताव आते हैं, तो ऐसे मामलों में वित्तीय सुविधाएँ एवं लोन दिलाकर लाभान्वित कराया जायेगा। बैठक में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों ने अपने–अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याएँ एवं सुझाव रखे। मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि वे उनकी समस्याओं को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर हल कराएंगे तथा सुझावों पर भी विचार विमर्श कर निर्णय लेंगे।

बैठक में विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री रमाकांत भार्गव के अलावा श्री विवेक चतुर्वेदी श्री सुभाष मानगे, श्री कैलाश पाटीदार, श्री राजकुमार रायजादा, श्री किशन सिंह भटोल, श्री शिवनारायण पाटीदार, श्री कौशल शर्मा, श्री रामविलास पटेल, श्री प्रकाशरत्न पारखी, श्री महाबली गौतम, श्री संजय श्रीवास, श्री अशोक टेकाम, श्री रामसिंह पटेल, श्री अरूण सिंह तोमर, श्री उमाकांत दीक्षित, श्री श्यामसुंदर शर्मा, श्री भरत सिंह, श्री राजेन्द्र गुरूजी, श्री शेखर किवे, श्री उमानारायण पटेल, उपस्थित थे।

प्रदेश के किसान अपने परिश्रम से आत्मनिर्भर अभियान को बनायेंगे सफल : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री पटेल ने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के आत्म–निर्भर भारत अभियान संबंधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सहभागिता करते हुए विश्वास दिलाया कि प्रदेश के किसान 'अभियान' को सफल बनाने में दृढ़–संकल्पित होकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसले ले रही है। निश्चित ही इन फैसलों से किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि आधारित व्यवसायों को भी गति मिलेगी। कृषि का आधारभूत ढाँचा मजबूत होगा तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मंत्री श्री पटेल ने आत्म–निर्भर भारत अभियान में कृषि के एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिये प्रधानमंत्री और केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के प्रमाण-पत्र वितरित

भोपाल। गृह, जेल एवं संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के ग्राम कटीली नुनवाहा, ग्राम कुम्हेड़ी एवं ग्राम रिछारी में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने ग्राम कटीली में 190 स्ट्रीट वेंडर को प्रमाण–पत्र वितरित किये। इन्हें 10–10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त लोन रोजगार शुरू करने के लिये दिया जाएगा। डॉ. मिश्र ने ग्राम नुनवाहा में 119, ग्राम कुम्हेड़ी में 106, और रिछारी में 64 स्ट्रीट वेंडर को प्रमाण–पत्र वितरित किये।

मंत्री डॉ. मिश्र ने ग्राम कुम्हेड़ी में विकास कार्यों के लिये 60 लाख रूपये और ग्राम रिछारी के लिये 26 लाख रूपये स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक गरीब व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेशके लिए आत्मनिर्भर गांव

टाइम एण्ड मोशन स्टडी शीघ्र करवाकर बढ़वाएं मनरेगा की मजदूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए ग्रामों का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने में मनरेगा योजना अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है। योजना में इस वर्ष 20.50 करोड़ मानव दिवस का लेबर बजट केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत 40 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान है। ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना बनाकर एवं समयबद्ध रूप से कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत प्रति दिवस मजदूरी दर 190 रूपये रूपये है, जबकि दूसरे राज्यों महाराष्ट्र में 238 रूपये, गुजरात में 224, राजस्थान में 220 तथा हरियाणा में सर्वाधिक 290 रूपये है। यह दर केन्द्र द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रदेश की मनरेगा मजदूरी दर बढ़वाने के लिए आवश्यक 'टाइम एण्ड मोशन स्टडी' शीघ्र करवाई जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में मनरेगा कार्य संबंधी समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, एसीएस श्री मनोज श्रीवास्तव उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री राम खिलावन पटेल वी.सी. से बैठक में शामिल हुए।

कार्यों की गुणवत्ता अच्छी हो, कार्यों का सही मूल्यांकन हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हों, समय से पूर्ण हो जाएं तथा पूर्ण हुए कार्य उपयोग में आने लगें। मनरेगा कार्यों का सही मूल्यांकन भी सुनिश्चित किया जाए।

79 प्रतिशत जॉब कार्डधारी कार्य कर रहे हैं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत 79 प्रतिशत जॉब कार्डधारी कार्य कर रहे हैं। यह अच्छा प्रतिशत है। अन्य राज्यों उत्तरप्रदेश में 57 प्रतिशत, पश्चिम बंगला में 72 प्रतिशत, राजस्थान में 73 प्रतिशत तथा बिहार में 36 प्रतिशत सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं।

हर गांव में शांति धाम

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने बताया कि मनरेगा से प्रदेश के छोटे–बड़े प्रत्येक गांव में शांतिधाम बनवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस कार्य की सराहना की।

समय पर हुआ मजदूरी का भुगतान

प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत समय पर मजदूरी भुगतान का प्रतिशत भी गत 5 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक रहा है। वर्ष 2020–21 में यह 93 प्रतिशत रहा। जबकि वर्ष 2019–20 में समय पर मजदूरी भुगतान का प्रतिशत 84.19 प्रतिशत मात्र था।

अब तक हुए 2 लाख 87 हजार कार्य पूर्ण

मनरेगा के तहत प्रदेश में अब तक 2 लाख 87 हजार कार्य पूर्ण हो चुके हैं। गत वर्ष इस अवधि तक पूर्ण हुए कार्यों की संख्या एक लाख 64 हजार तक ही सीमित रही।

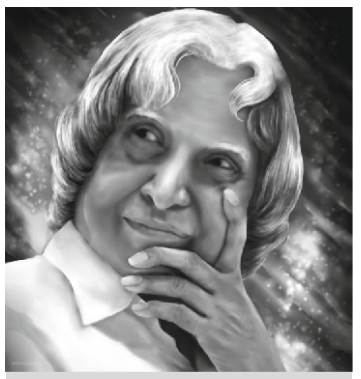

विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए।

– अब्दुल कलाम

किसानों की फसलों को 'यलो मोजेक' से बचाने के लिए तत्परता से कार्रवाई करे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषि विभाग एवं कलेक्टर्स को दिए निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के कई स्थानों से सोयाबीन की फसल में 'यलो मोजेक' कीट लगने की सूचना आई है। यह बहुत गंभीर बात है। कृषि विभाग इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करते हुए फसलों की इससे सुरक्षा के हरसंभव उपाय करें, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान न हो। सभी कलेक्टर्स अपने जिलों में इसकी रोकथाम के उपाय सुनिश्चित कराएं। कार्य में थोड़ी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सोयाबीन कृषकों के लिये कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

सोयाबीन उत्पादन करने वाले कृषकों को सलाह दी गई है कि पीला मोजाइक पर नियंत्रण के लिये प्रारंभिक अवस्था में ही अपने खेत में जगह–जगह पर पीला चिपचिपा ट्रैप लगाएं जिससे इसका संक्रमण फैलाने वाली सफेद मक्खी का नियंत्रण होने में सहायता मिले। इसके रोकथाम के लिए फसल पर पीला मोजाइक रोग के लक्षण देखते ही ग्रसित पौधों को अपने खेत से निष्कासित करें। ऐसे खेत में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए अनुशंसित पूर्व मिश्रित सम्पर्क रसायन जैसे बीटासायफ्लुथ्रिन + इमिडाइ– क्लोप्रिड (350 मिली/हेक्टेयर) या पूर्व मिश्रित थायोमिथाक्सम + लैम्बडा सायहेलोथ्रिन (125 मिली/हेक्टेयर) का छिड़काव करें जिससे सफेद मक्खी के साथ–साथ पत्ती खाने वाले कीटों का भी एक साथ नियंत्रण हो सकें।

कुछ क्षेत्रों में लगातार हो रही रिमझिम वर्षा की स्थिति में पत्ती खाने वाली इल्लियों द्वारा पत्तियों के साथ–साथ फलियों को भी नुकसान पहुँचा रही है जिससे अफलन जैसी समस्या होने की संभावना है। पत्तियाँ खाने वाली इल्लियों के नियंत्रण के लिये संपर्क कीटनाशक जैसे इन्डोक्साकार्ब 333 मिली/हेक्टेयर या लैम्बडा सायहेलोथ्रिन 4.9 सीएस 300 मिली/हेक्टेयर का छिड़काव करें। कीटनाशक को प्रभावी ढंग से इल्लियों तक पहुँचाने के लिए नैपसेक स्प्रेयर से 500 लीटर या पॉवर स्प्रेयर से 120 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर का उपयोग अवश्य करें। यदि पत्ती खाने वाली इल्लियों के साथ–साथ सफेद मक्खी का प्रकोप हो, कृषकों को सलाह हे कि नियंत्रण के लिये बीटासाय–फ्लुथ्रिन + इमिडा– क्लोप्रिड 350 मिली/ हेक्टेयर, या थाय–मिथोक्सम + लेम्बडा सायहेलोथ्रिन 125 मिली/ हेक्टेयर का छिड़काव करें।

सोयाबीन की फसल में नुकसान करने वाले अन्य कीटों से बचाव के लिये कृषकों को सलाह है कि अपने खेते में फसल निरीक्षण के उपरांत पाए गए कीट विशेष के नियंत्रण के लिए अनुशंसित कीटनाशक की मात्रा को 500 लीटर/हेक्टेयर, की दर से पानी के साथ फसल पर छिड़काव करें। छिड़काव के लिये पावर स्प्रेयर का उपयोग किये जाने पर 120 लीटर/हेक्टेयर पानी की आवश्यकता होगी एवं छिड़काव भी प्रभावकारी होगा। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में फफूंदजनित एन्थ्रेकनोज तथा राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाईट नामक बीमारी का प्रकोप होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतरू इनके नियंत्रण के लिये सलाह है कि टेबूकोनाझोल (625 मिली/हेक्टैयर) अथवा टेबूकोनाझोल + सल्फर (1 किग्रा/हेक्टेयर) अथवा पायरोक्लोर्स्टोबीन 20 डब्ल्यूजी (500 ग्राम/हेक्टैयर) अथवा हेक्जाकोनाझोल 5 प्रतिशत ईसी (800 मिली/हेक्टेयर) से छिड़काव करें।

संबल योजना को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के निर्देश

श्रम विभाग की समीक्षा श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने की

भोपाल। श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रदेश के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण संबंल योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए रोजगार पोर्टल पर सरल हिन्दी भाषा में यूजर मेन्युअल एवं डेमों को दर्शाया जाये। जिससे सामान्य व्यक्ति को भी पंजीयन कराने में कोई कठिनाई न हो। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि रोजगार सेतु पोर्टल की सुविधाओं को एप के माध्यम से प्राप्त करने के लिए एन.आई.सी के सहयोग से सरलीकृत माबईल एप का निर्माण भी किया जाये।

मंत्री श्री सिंह ने श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा बनाये जा रहे उन्नति पोर्टल एवं अन्य राज्यों के पोर्टल का अध्ययन कर उनके आधार पर मध्यप्रदेश के रोजगार सेतु पोर्टल को अद्यन किया जाये, साथ ही भारत सरकार के उन्नति पोर्टल के साथ एकीकरण किया जाये, जिससे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को उन्नति पोर्टल की सेवाओं का लाभ मिल सकें। उन्होंने कहा कि रोजगार सेतु पोर्टल का प्रचार–प्रसार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा किया जाये, जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों को इसका लाभ मिल सकें। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जानकारी के आभाव में राज्य में वापस आये प्रवासी श्रमिक जो पंजीयन से वंचित रह गए हो, उनके लिए रोजगार और अन्य योजनओं का लाभ लेने के लिए सीमित अवधि के लिए रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध करवायी जाये।

प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत इस वर्ष तीन गुना काम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मनरेगा मजदूरों से वी.सी. के माध्यम से बातचीत की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष मनरेगा योजना के अंतर्गत 7 लाख 81 हजार कार्य खोले जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना हैं। इन कार्यों में अभी तक 79 लाख 80 हजार श्रमिकों को रोजगार दिलाया गया है। गत वर्ष आज की स्थिति में 47 लाख 75 हजार मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिया गया था। इस वर्ष बड़ी संख्या में मजदूरों को कार्य दिये जाने के साथ ही किए जा रहे कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं बहुत उपयोगी हैं। मनरेगा के अंतर्गत धार जिले के सूलीबर्डी गांव में फॉसिल पार्क, श्योपुर जिले के रायपुरा में बावड़ी जीर्णोद्धार, ग्वालियर जिले के बन्हेरी में गो–शाला निर्माण तथा बालाघाट जिले में नहर गहरीकरण के कार्य अनूठे एवं अद्भुत हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के मनरेगा के मजदूरों से उनके कार्य स्थल से ही चर्चा कर रहे थे। वी. सी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री राम खिलावन पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, एसीएस श्री मनोज श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

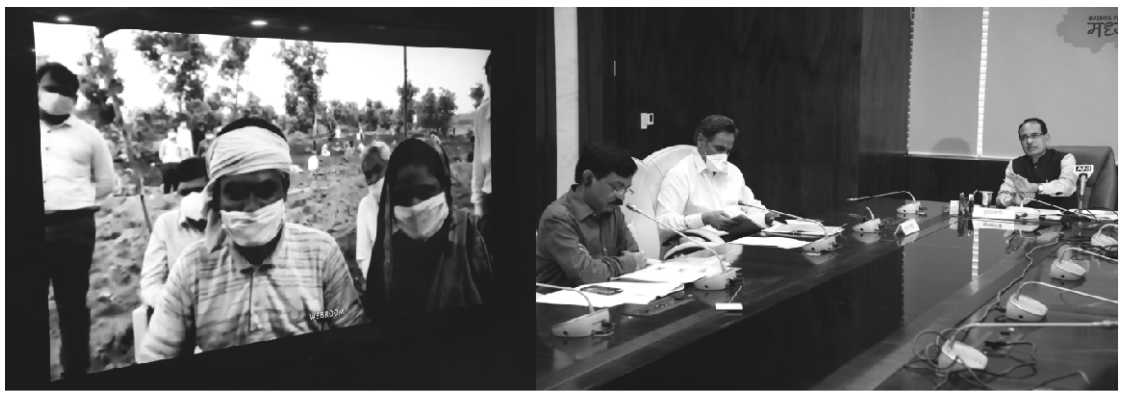

गौ–शाला के शुभारंभ के लिए खुद आऊंगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान को ग्राम बन्हेरी जिला ग्वालियर के श्री अजब सिंह एवं हरी रावत ने बताया कि वे ग्राम में तैयार की जा रही है गो–शाला में कार्य कर रहे हैं। उन्हें समय पर कार्य की मजदूरी भी प्राप्त हो गई है। मनरेगा से बनाई जा रही इस गौशाला में 1500 गौवंश को रखने की व्यवस्था रहेगी। गो–शाला के साथ ही मंदिर सरोवर का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि गो–शाला के शुभारंभ के लिए वे स्वयं बन्हेरी आएंगे।

मनरेगा से तैयार की नक्षत्र वाटिका

बैतूल जिले के ग्राम कान्हाबाड़ी की कान्ति देवी ने मुख्यमंत्री को बताया कि गाँव में मनरेगा से नक्षत्र वाटिका तैयार की गई है जिसमें 27 नक्षत्र, 12 राशि एवं 9 ग्रहों के पौधे रोपित किए गए हैं। वाटिका में एक्यूप्रेशर ट्रेक एवं पाथ–वे भी बनाया गया है। इसमें गांव की महिलाओं ने मिस्त्री का कार्य किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य के लिए कान्ति देवी सहित सभी को बधाई दी।

पहले महाराष्ट्र में काम करते थे अब यहीं करेंगे

कसाराघाट कल्याण महाराष्ट्र से वापस लौटे प्रवासी मजदूर श्री रामचरण ने बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने गांव रोशिया जिला खंडवा लौट आए। लौटते ही उनका एवं उनकी पत्नी बिन्दु बाई का जॉब कार्ड बन गया। अब वे दोनों मनरेगा में खंती खुदाई (कंटूर ट्रेंचिंग) का कार्य कर रहे हैं। आगे भी अपने गांव में रहकर ही काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी उन्हें काम मिलता रहेगा।

काम मिला, मजदूरी मिली, राशन मिला, मास्क भी मिला

मुरैना जिले के ग्राम धनेला के राजू जाटव ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि उन्हें मनरेगा में काम मिला है, समय पर मजदूरी मिल रही है, फ्री राशन मिला और मास्क भी मिला। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने निरूशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है, वे अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं।

317 सिंचाई नहरों का गहरीकरण

मुख्यमंत्री श्री चौहान को बालाघाट जिले के ग्राम पाला के सुमित खरे ने बताया कि गावँ में वे मनरेगा में नहर गहरीकरण का कार्य कर रहे हैं। पहले नागपुर में मिस्त्री का कार्य करते थे। एसीएस श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि बालाघाट जिले में मनरेगा से 317 सिंचाई नहरों के गहरीकरण का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य की प्रशंसा की।

'फॉसिल पार्क' देखने जरूर आऊंगा

ग्राम सुलीबर्डी जिला धार के अनसिंग गंगाराम ने बताया कि गांव में मनरेगा से ष्फॉसिल पार्कष बनाया गया है, जिसमें वे मजदूरी कर रहे हैं। एसीएस श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में फॉसिल (जीवाश्म) उपलब्ध हैं, जिन्हें इस पार्क में संग्रहित किया गया है। यहां डायनासोर के अंडों सहित अन्य दुर्लभ जीवाश्म (फॉसिल) हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह अद्भुत कार्य है। मैं इसे देखने जरूर आऊंगा। उन्होंने कार्य के लिए संबंधित सभी को बधाई दी।

वेबीनार : आधुनिक संगोष्ठी

वेबीनार शब्द वेब तथा सेमिनार से मिलकर बना है। वेबीनार में वीडियो वर्कशॉप, व्याख्यान या प्रजेंटेशन को वेबीनार सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ऑनलाईन होस्ट किया जाता है। वेबिनार का उपयोग व्यापार संबंधित, शिक्षा संबंधित, कार्यालय संबंधित या किसी अन्य विषय पर दुनियां भर के लोगो के साथ विचार विमर्श के लिये किया जाता है। वेबीनार सेमिनार का ही वेब वर्जन होता है अतः इसमें प्रतिभागियो का एक जगह इक्कठा होना आवश्यक नही होता है। कोरोनाकाल में इसका बहुत उपयोग हो रहा है।

वेबीनार आयोजित करने के लिये वेबीनार सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। स्काईप, गूगल मीट, वेबएक्स, जूम आदि लोकप्रिय वेबीनार सॉफ्टवेयर है, जो उपयोग के लिये निःशुल्क उपलब्ध है। आयोजनकर्ता को उपयुक्त सॉफ्टवेयर पर जाकर न्यू मिटिंग को चुनना होता है जिससे उसे मिटिंग की लिंक प्राप्त होती है। वह इसमें इच्छित पासवर्ड भी ले सकता है। अब आयोजनकर्ता द्वारा प्रतिभागियो को फोन, एसएमएस, व्हाट्सअप या ईमेल द्वारा मीटिंग की तारीख, समय, लिंक, पासवर्ड, विषयवस्तु तथा वेबीनार सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जाती है। होस्ट को निर्धारित तारीख व समय पर सॉफ्टवेयर का संचालन करना होता है। प्रतिभागियो द्वारा जुडने के लिये भेजी गई प्रार्थना को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है। प्रतिभागियों का ऑडियो तथा विडियो को बंद तथा चालू किया जा सकता है। होस्ट द्वारा प्रतिभागी को मीटिंग से बाहर भी किया जा सकता है। प्रस्तुतकर्ता द्वारा ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन तथा व्हाईट बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से अपना प्रस्तुतीकरण दिया जा सकता है। प्रतिभागियो के सवालों का जवाब भी दिया जा सकता है। प्रतिभागियो द्वारा मीटिंग के दौरान टेक्सट मेसेज भी टाईप किये जा सकते है जो सभी को उनकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे।

वेबीनार का लाभ यह है कि बहुत कम लागत व समय में विश्वभर के प्रतिभागियों के लिये वर्चुअल मिटिंग का आयोजन सरलता से किया जा सकता है। वेबीनार को रिकार्ड भी किया जा सकता है। वेबीनार की कमी यह है कि इसमें प्रतिभागी सम्मुख उपस्थित नही होने के कारण इतना प्रभावी नही होता है। प्रतिभागी प्रस्तुतीकरण को कितना समझ पा रहे है इसका अनुमान लगाना प्रस्तुतकर्ता के लिये मुश्किल होता हे। यदि कोई प्रतिभागी अपना ऑडियो विडियो बंद कर दे तो वह डिजिटल तो उपस्थित रहता है लेकिन फिजिकल अनुपस्थित रह सकता है। यदि किसी प्रतिभागी के पास थोडा पुराना उपकरण व नेट है तो उसके ऑडियो वीडियो में दिक्कते आती है। चूकि यह एक विडियो मीटिंग है तो इसमें नेट का डाटा ज्यादा खर्च होता है। वेबीनार सॉफ्टवेयर की क्षमता से ज्यादा प्रतिभागियो को जोडा नही जा सकता है।

वेश्विक महामारी कोरोना के कारण देश की शैक्षणिक संस्थाऐं बंद है लेकिन वेबीनार के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य जारी है। कोरोना के कारण देश में आवागमन की सुविधायें सीमित उपलब्ध है, ऐसी परिस्थिति में कार्यालयों द्वारा अपने कर्मचारियों की वेबीनार के द्वारा मिटिंग ली जा रही है। सरकार द्वारा वेबीनार के माध्यम से विभागों की समीक्षा की जा रही है। प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा भी वेबीनार के माध्यम से प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर संकट की इस घडी में वेबीनार ने सबको जोडने व कार्य जारी रखने में बहुत मदद की है। आने वाले समय में वेबीनार सामान्य बात हो जायेगी व कोरोना समाप्ति के बाद भी इसका उपयोग अत्याधिक किया जाता रहेगा। जय सहकारिता।

शिरीष पुरोहित, कम्प्यूटर प्रशिक्षक
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर

जिला सहकारी संघ में अध्यक्ष श्री जोशी द्वारा ध्वजारोहण

रतलाम। जिला सहकारी संघ मर्यादित, रतलाम के कार्यालय पर संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान एवं मध्यप्रदेश गान का वाचन किया गया। पश्चात संघ के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा 'सहयोग से सुरक्षा अभियान' के अंतर्गत कोराना वायरस से संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु शपथ पत्र. के माध्यम से संकल्प लिया गया।

इस अवसर पर जिले के उपायुक्त सहकारिता एवं बैंक प्रशासक परमानंद गोडरिया, जिला सहकारी संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिरूद्ध शर्मा, संघ के जनसम्पर्क अधिकारी पिंकेश भट्ट, विश्वास शर्मा, सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के.सी. मोदी, बी.एस. चौहान, आर.के. सोनी, जे.सी. जोनवाल, आर.सी. बामनिया, एम.सी. मालवीय, एन.के. जैन, आर.के. खन्ना, अमरसिंह राठौर, विजयसिंह परिहार, श्री मावर, विकास खराड़े, नीता वर्मा, आशीष लोहार, दिपीका केमा, सुनीता गोयल, हरीश चौहान, जीमल खान, हेमन्त सक्सेना, मगन लाल आदि उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है

स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने झंडावंदन कर सलामी ली

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउण्ड परिसर के मोतीलाल नेहरु स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला विशेष सशस्त्र बल, जिला बल, शासकीय रेल पुलिस, विशेष शस्त्रबल हॉक फोर्स, एस.टी.एफ., नगर सेना, जेल विभाग और पुलिस बैंड की टुकड़ियों से सज्जित परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं सभी उपस्थितों द्वारा भारतमाता की जयघोष के साथ मुख्यमंत्री का संबोधन प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवाने वाले वीर बलिदानियों के चरणों में नमन करते हुए कहा कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वालों के सम्मान में भोपाल में निर्मित शौर्य स्मारक में आज भारतमाता की प्रतिमा स्थापित हुई है। यह सभी को राष्ट्र प्रेम, शौर्य और साहस की प्रेरणा देगी। प्रत्येक नागरिक को भोपाल के शौर्य स्मारक में स्थापित इस प्रतिमा के दर्शन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण किया तथा उनके कथन को उद्धृत किया कि ष्भारतभूमि सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। यही जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है, कश्मीर किरीट है, गौरीशंकर इसकी शिखा है। पंजाब और बंगाल इसकी दो बाहु हैं। दिल्ली दिल है। विंध्याचल कटि है। नर्मदा करधनी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके पंजे हैं। सागर इसके पग पखारता है। पावस के कुंतल मेघ, काले–काले मेघ केश राशि हैं। सूर्य और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है। ये तर्पण की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर–कंकर शंकर है। इसका बिन्दु–बिन्दु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। मरने के बाद जब अस्थियाँ विसर्जित होंगी तो जल से आवाज आएगी, भारत माता की जय। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश के यशस्वी एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। अब यह वर्ष 1962 का भारत नहीं है। यदि किसी शत्रु ने भारत की ओर आँख उठाकर देखा तो उसे सबक सिखाने में भारत पीछे नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को एक करोड़ रुपये की राशि, परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा और भूखंड प्रदान करने का निर्णय लेकर बलिदानियों के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने चमत्कारी नेतृत्व से असंभव माने जाने वाले कार्यों को संभव कर दिखाया है। कोरोना की चुनौती का उनके सक्षम नेतृत्व में देश ने साहस के साथ सामना किया, देश में सुनियोजित व्यवस्थाएं की गईं और उस पर प्रभावी नियंत्रण किया है।

मध्यप्रदेश के अमर शहीद दीपक को श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारी सीमा पर अतिक्रमण करने का दुस्साहस करने वालों को हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की परवाह न कर मुँहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय में मध्यप्रदेश के रीवा जिले के फरेदा गाँव के सैनिक श्री दीपक सिंह ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। उन्हें सादर श्रद्धांजलि।

संबल योजना गरीबों का 'सुरक्षा कवच'

मध्यप्रदेश, देश का ऐसा कल्याणकारी राज्य है, जहाँ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को संबल योजना के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा कवच दिया गया है। विगत चार माह में योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लगभग 25 हजार से अधिक हितग्राहियों को लगभग 268 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

'वन नेशन–वन राशन कार्ड' योजना

राज्य सरकार वन नेशन–वन राशन कार्ड की महत्वाकांक्षी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के ऐसे 24 श्रेणियों के पात्र लगभग 37 लाख हितग्राही, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें भी 31 अगस्त, 2020 तक पात्रता पर्ची जारी कर निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय किया जाने का महाभियान प्रारंभ किया गया है।

रिकार्ड गेहूँ उपार्जन

सरकार ने 15 अप्रैल से गेहूँ उपार्जन का कार्य प्रारंभ किया, जो एक बड़ी चुनौती थी। किसान भाइयों के सहयोग से उपार्जन में हम देश में नंबर एक बन गए हैं। पंजाब को पीछे छोड़ते हुए एक करोड़ 29 लाख 42 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ लगभग 15 लाख 81 हजार किसानों से उपार्जित किया गया। किसानों को 24 हजार 800 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी समय पर किया गया।

शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण

किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना सतत जारी रखी गई है। हमारी सरकार ने वर्ष 2018–19 की फसल बीमा की प्रीमियम राशि 2200 करोड़ रुपये का भुगतान बीमा कंपनियों को किया, जिससे 16 लाख किसानों को फसल हानि के 3100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्ष 2019–20 के प्रीमियम का भी भुगतान किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप किसानों को 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान होगा।

मंडी अधिनियम में संशोधन

किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मण्डी अधिनियम में संशोधन किए गए। एक ही लायसेंस से व्यापार करने, निजी क्षेत्र में मण्डियों की स्थापना एवं कृषि उपज को किसान के द्वार से सीधे खरीदने की सुविधा दी गई है।

एक हजार नवीन कृषक उत्पादक संघ

आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश अभियान के अंतर्गत अगले तीन वर्ष में प्रदेश में 1000 नवीन कृषक उत्पादक संगठनों का सृजन कर इन्हें पूँजी अनुदान, क्रेडिट गारंटी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित की जाएंगी।

प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोरोना से बचाव

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सही समय पर लिए गए सुविचारित निर्णयों के परिणामस्वरूप भारत ने कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में प्रभावी कार्य किया। श्री मोदी मैन ऑफ़ आइडियाज हैं। कठिन चुनौती भरे समय को अवसर के रूप में लेते हुए उन्होंने आत्म–निर्भर भारत का जो मंत्र दिया है उस पर प्रदेश तेज गति से चल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्रमुख घोषणाएँ

- निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय का महाअभियान आरंभ होगा।
- 'मेधावी विद्यार्थी योजना' तथा सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था।
- मेधावी विद्यार्थियों को वितरित होंगे लैपटॉप।
- प्रदेश में प्रारंभ होंगे सर्व–सुविधायुक्त और गुणवत्तापूर्ण 'सीएम राइज स्कूल'
- महिला स्व–सहायता समूहों को इस वर्ष 1300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाएगा।
- 'एक जिला एक उत्पाद' के सिद्धांत पर होगी जिलों की ब्रांडिंग।
- बेटियों की पूजा से आरंभ होंगे शासकीय कार्यक्रम। बेटी बचाओ अभियान नए सिरे से प्रारंभ होगा।
- आदिवासियों एवं गरीबों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान। नियमों के विपरीत 15 अगस्त 2020 तक दिए गए ऋण शून्य होंगे। आवश्यक कानून लाया जाएगा।
- पुलिस कर्मियों के लिए भोपाल में बनेगा 50 बिस्तरीय सर्व–सुविधायुक्त अस्पताल।
- 2023 तक 1 करोड़ नल कनेक्शन का लक्ष्य। हर घर तक नल के माध्यम से जल।
- सभी नागरिक सुविधाएँ ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएंगी।
- नर्मदा एक्सप्रेस–वे से नर्मदांचल में उद्योगों, ईको टूरिज्म और धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहन।
- नये उद्योगों की स्थापना में सरलता के लिए 'स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज' योजना प्रारंभ होगी।
- प्रदेश के नागरिकों का 'सिंगल सिटीजन डाटाबेस' तैयार होगा।
- ग्रामीण जनता को उनके आवासीय भूखंड पर मालिकाना हक दिया जाएगा।
- कर्मचारियों को देय सभी लाभ दिए जाएंगे।
- कोरोना काल की तरह आगे भी गरीबों के लिए सस्ती बिजली।

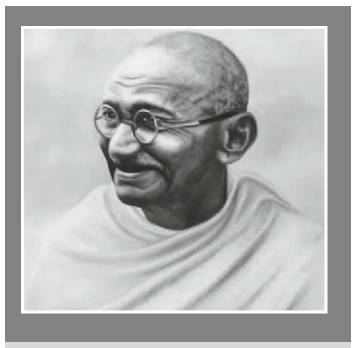

खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, उसमें सामंजस्य हों।
– महात्मा गांधी

आत्मनिर्भर भारत पैकेज का मध्यप्रदेश पूरा उपयोग करेगा : मंत्री श्री सखलेचा

सितंबर में हर जिले में सेमिनार होंगे–नव उधमियों को मौके मिलेंगे

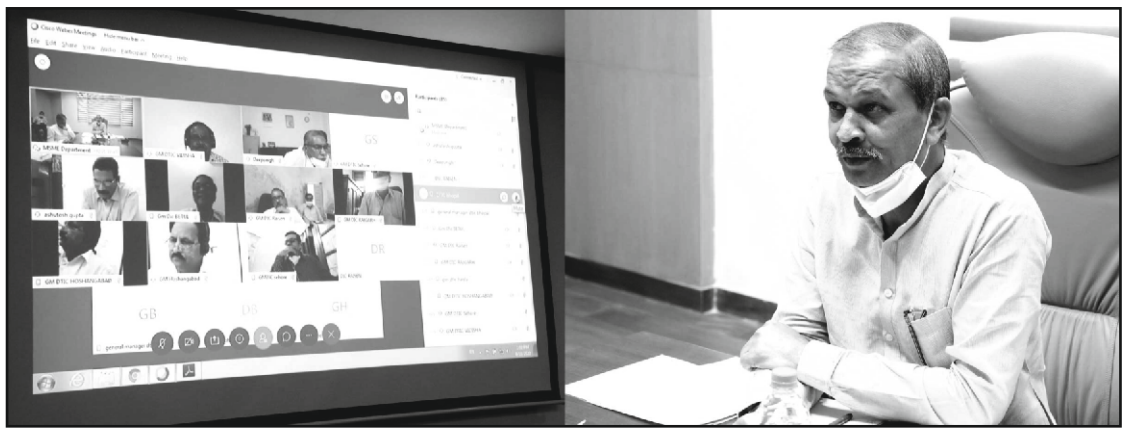

भोपाल। मध्यप्रदेश में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए सितंबर माह में जिला वार सेमीनार आयोजित किए जाएंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने आज मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई के लिए दिए गए महत्वपूर्ण पैकेज का प्रदेश के नव उद्यमियों के लिए भरपूर उपयोग किया जाएगा।

मंत्री श्री सखलेचा ने उद्योग अधिकारियों से कहा है कि उनके क्रियाकलाप केवल औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। स्वयं उद्योग चलाने वालों की भी सरकार संकट के समय मदद करेगी। उन्होंने कहा कि वे हर सप्ताह मैदानी स्तर के कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 25 करोड़ तक की ऋणी इकाइयों को पुनः 20 प्रतिशत लोन की सुविधा का जरूरतमंद कारोबारियों को लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। अब तक इस स्कीम से लाभान्वितों की समीक्षा अगली बैठक में होगी।

बंद और बीमार इकाईयों को शुरू कराएं

मंत्री श्री सखलेचा ने सभी उद्योग अधिकारियों के साथ अनेक जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में बीमार और बंद पड़ी इकाइयों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उद्यमियों से व्यक्तिगत संपर्क कर कारणों की जानकारी प्राप्त कर यह पता लगाया जाए कि बंद इकाई को किस तरह की मदद से फिर सुचारू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को चालू कराएं।

मंत्री श्री सकलेचा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले माह होने वाले सेमिनार के पूर्व अपने क्षेत्रों में लगने वाली इकाइयों की रूपरेखा स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसाईयों, कृषक और उद्योग लगाने के इच्छुक युवाओं से सतत संपर्क कर रणनीति बनाएं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध भूमि की जानकारी तैयार करें और नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित भूमि का कब्जा लें। उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय करें और प्रदेश की उद्योग नीति के अनुरूप रूपरेखा तैयार करें जिससे सेमिनार में ही अनेक इकाइयों के स्थापना की शुरुआत हो सके।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्षेत्र विशेष की खासियत और उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा भी की गई।

अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का लोकार्पण

70 करोड़ 54 लाख की लागत से बनी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने रविवार को सागर में मसवासी ग्रंट में अत्याधुनिक एकीकृत ठोस प्रबंधन इकाई के लोकार्पण के साथ ही प्रदेश में 'गंदगी भारत छोड़ो–मध्यप्रदेश' अभियान का शुभारंभ किया। इस इकाई की लागत 70 करोड़ 54 लाख रूपये है। सबसे अहम बात यह है कि यहां पर प्रदेश का पहला एनीमल कारकस प्लांट भी लगाया गया है, जहाँ मृत मवेशियों के शवों को वैज्ञानिक ढंग से डिस्पोज किया जायेगा। 'गंदगी भारत छोड़ो–मध्यप्रदेश' अभियान 16 से 30 अगस्त तक चलेगा।

मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया की प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। उन्होंने कहा कि कचरे के परिवहन के समय गाँव के लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और कटनी मे इस तरह के प्लांट संचालित हैं, लेकिन सागर का यह प्लांट आधुनिकतम मशीनों से लैस है। प्लांट में सागर नगर निगम सहित जिले के 10 नगरीय निकाय खुरई, मकरोनिया, राहतगढ़, बीना, देवरी, बंडा, गढ़ाकोटा, रहली, शाहपुर, शाहगढ़ से निकलने वाले कचरे का निष्पादन किया जायेगा और जैविक खाद तैयार की जायेगी। प्लांट संक्रामक बिमारियों से रोकथाम और सागर को कचरा मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य व समृद्धि के लिये स्वच्छता आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दिशा में देश और प्रदेश को गंदगी मुक्त बनाने के लिए लगातार कार्य किया है। इसी का परिणाम है कि देश के सबसे स्वच्छ शहरों में प्रथम और द्वितीय स्थान रखने वाले शहर इंदौर, भोपाल मध्यप्रदेश के हैं। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में मध्यप्रदेश के शहरों में कचरे के ढेर देखने को नही मिलेंगे। शहरों की गंदगी सबसे बड़ी समस्या है। इसे हमे चुनौती के रूप में लेना है।

मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण व रोकथाम के लिये मध्यप्रदेश में सरकार ने बेहतर कार्य किया है। जिसके फलस्वरूप आज मध्यप्रदेश 15 वे स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रतिदिन कोरोना नियंत्रण की समीक्षा करते हैं। उन्होंने विभिन्न सत्रों में अब तक 600 से अधिक घंटे कोरोना की समीक्षा की है। प्रदेश में कोरोना का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सागर में कोरोना नियंत्रण का अच्छा कार्य हुआ है।

5 लाख लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित

मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि कोरोना बचाव के लिये प्रदेश में चलाये गए 'एक मास्क–अनेक जिन्दगी' अभियान के तहत 5 लाख लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित किये गए हैं। उन्होंने कहा चलाये जाने वाले गंदगी भारत छोड़ों अभियान के तहत नगरीय निकायों की रैकिंग की जायेगी और अच्छा कार्य करने वाली नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री से सम्मानित करवाया जायेगा। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सागर के विकास में फन्ड की कोई कमी नहीं होगी और मकरोनिया को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जायेगा।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में ध्वजारोहण

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर में प्राचार्य श्री दिलीप मरमट ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में प्राचार्य श्री शशिकांत चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत 8 हजार 850 करोड़ का निजी निवेश होगा

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री डंग ने बैठक ली

भोपाल। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश–वेबिनार में प्राप्त सुझावों के अनुरूप वर्ष 2021–22 में प्रदेश में 8 हजार 850 करोड़ का निजी निवेश अनुमानित है। इसके तहत 1500 मेगावाट के सोलर पार्क, 600 मेगावाट के ओंकारेश्वर के फ्लोटिंग सोलर पार्क, 30 मेगावाट का सोलर रूफटॉप के साथ–साथ 200 ई.व्ही. चार्जिंग स्टेशन प्रस्तावित हैं।

श्री डंग मंत्रालय में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपरोक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिये सभी जरूरी कदम पूरी प्रतिबद्धता के साथ उठाये जायें। मंत्री श्री डंग ने प्रस्तावित सौर पार्क से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री दीपक सक्सेना तथा अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। भूमि की उपलब्धता के संबंध में श्री सक्सेना ने प्रकाश डाला। मंत्री श्री डंग ने जानना चाहा कि प्रस्तावित सौर पार्क कब तक चालू हो सकेगा और इस सिलसिले में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं।

बैठक में मंत्री श्री डंग ने पी. एम. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम–अ) के बारे में भी अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा–निर्देश दिये। प्रबंध संचालक श्री सक्सेना ने बताया कि इसके तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के विद्युत उत्पादन की योजना है। साथ ही मंदसौर में 915 सब स्टेशन पर 300 मेगावाट की सोलर परियोजना का लक्ष्य है।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री डंग ने मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना (पी.एम. कुसुम–ब) से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी तलब की। अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि लक्ष्य पूर्ति के लिये मध्यप्रदेश शासन का अंश लगभग 263 करोड़ रुपये आकलित है। प्रबंध संचालक श्री सक्सेना ने बताया कि मंदसौर जिले में 262 कार्यादेश जारी हो चुके हैं तथा 178 सोलर पम्पों की स्थापना हो गई है। इसी प्रकार पी.एम. गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 256 पम्पों की स्थापना की जा चुकी है। मंत्री श्री डंग ने निर्देशित किया कि जारी किये गये कार्यादेश पर शीघ्र पम्प स्थापना के लिये कदम उठाये जायें।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के नीमच में 500 मेगावाट क्षमता, आगर में 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 मेगावाट, छतरपुर में 1500 मेगावाट, मुरैना में 1400 मेगावाट तथा ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता के प्रस्तावित सौर पार्क को मूर्त रूप दिया जायेगा।

मंत्री श्री डंग ने रेस्को मॉडल आधारित सौर संयंत्र रूफटॉप के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में अधिकारियों से ब्यौरा तलब किया। मौजूद अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रस्ताव आमंत्रण के लिये ईओआई जारी किया जा चुका है।

बैठक में जानकारी दी गई कि आदिम–जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या परिसरों, आवासीय स्कूलों एवं आश्रमों में सौर गर्म जल संयंत्रों की स्थापना तथा डेयरी फेडरेशन द्वारा संचालित प्रदेश के 4 दुग्ध प्लांटों के बॉयलर को गर्म पानी प्रदाय करने के लिये भी सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना की कार्यवाही चल रही है। बैठक में मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण यंत्री श्री श्रीकांत देशमुख एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सभी यही कहते है गलती सफलता का पहला कदम है लेकिन मेरा मानना है की गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है।

– शिवानी दीदी

वनोपज संघ अध्यक्ष श्री गिरी ने किया ध्वजारोहण

भोपाल। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य लघु वनोपज संघ कार्यालय में अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र गिरी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर प्रबंध संचालक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

स्थानीय किसानों की मांग के अनुरूप फलोद्यान की योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित करें

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने दिए दिए निर्देश

भोपाल। उद्यानिकी विभाग की प्रदेश में फल–फूल एवं सब्जी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में स्थानीय किसानों की मांग के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। यह निर्देश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने मंत्रालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में दिए।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फल–फूल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। स्थान विशेष में जलवायु मिट्टी आदि की अनुकूलता को ध्यान में रख किसान फसलों का उत्पादन करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए उद्यानिकी विभाग की योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त जमीनी जानकारी को ध्यान में रख योजनाओं में फसलों के उत्पादन में किसानों को अनुदान सहायता देने के निर्धारित लक्ष्यों का फिर से निर्धारण करें। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि शाजापुर जिले में संतरा, बुरहानपुर जिले में केला का उत्पादन बहुतायत में हो रहा है। इन जिलों में किसानों को संतरा और केला की फसल उत्पादन के लिए योजनाओं में शामिल किया जाए।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इस वर्ष 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य है। योजना में 34 हजार कृषक लाभावन्त होंगे। बैठक में राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने मध्यप्रदेश सूक्ष्म सिंचाई योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्यप्रदेश अव्वल

भोपाल। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में मध्यप्रदेश देश में नंबर एक पर है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 58 हजार 476 स्ट्रीट वेंडर्स को 10–10 हजार रुपये का ब्याजमुक्त लोन स्वीकृत किया जा चुका है। यह देश में कुल स्वीकृत प्रकरणों का 47 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह के अंत तक एक लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स का लोन स्वीकृत कर दिया जायेगा। श्री सिंह ने यह जानकारी केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास और शहरी कार्य श्री हरदीप एस. पुरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान दी। समीक्षा में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्री और अधिकारी शामिल थे। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री पुरी ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना में किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि 378 नगरीय निकायों में 8 लाख 78 हजार स्ट्रीट वेंडर्स ने पंजीयन करवाया है। इनमें से 4 लाख 37 हजार से अधिक आवेदन सत्यापित किये जा चुके हैं। तीन लाख 77 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को परिचय–पत्र वितरित किये जा चुके हैं। लोन स्वीकृति हेतु विभिन्न बैंकों को एक लाख 70 हजार से अधिक प्रकरण भेजे जा चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश इस योजना में बेहतर कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अटल जी की पुण्य तिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्य तिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व. अटल जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में विकसित होने वाले चंबल एक्सप्रेस–वे (प्रोग्रेस–वे) का नाम अटल जी के नाम पर अटल प्रोग्रेस–वे होगा। इसके अलावा राजधानी भोपाल में अटल जी की भव्य और दिव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। स्व. अटल जी के जन्म दिवस 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रति वर्ष सुशासन से संबंधित कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों की रूपरेखा निर्धारित कर अटल जी को आदरांजलि दी जाएगी।

श्रद्धांजलि

भोपाल। श्री मनोज कुमार भारत सेवा निवृत्त व्याख्याता नहीं रहे। श्री भारत लम्बे समय से अस्वस्थ चल रहे थे तथा 30 जून 2020 को सेवा निवृत्त हुए थे। मध्यप्रदेश राज्य संघ मुख्यालय, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर तथा इंदौर में शोक सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिवार को इस असहनीय दुःख को वहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु प्रार्थना की गई।

कृषि अधोसंरचना कोष बदलेगा कृषि और किसानों की दशा : मुख्यमंत्री

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों से की चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस से केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कृषि अधोसंरचना कोष के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत चर्चा में हिस्सा लिया। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आत्मनिर्भर भारत अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना कोष के संबंध में राज्यों से चर्चा की और प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा किसानों की समृद्धि के लिए तैयार किए गए प्रकल्प को सफल बनाने का आव्हान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि अधोसंरचना कोष का अधिकाधिक लाभ किसानों को दिलवाने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की यह अद्भुत योजना है। मध्यप्रदेश सरकार इसके क्रियान्वयन में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसे जमीन पर उतारने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने ठोस प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं।

मध्यप्रदेश के प्रयासों का वीडियो कान्फ्रेंस में उल्लेख हुआ। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने मध्यप्रदेश में आत्मनिर्भर वेबिनार के माध्यम से कृषि अधोसंरचना कोष के प्रावधानों का लाभ लेने के लिए की गई अग्रिम पहल को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की इस वीडियो कान्फ्रेंस में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दोनों राज्यमंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश, गुजरात एवं अन्य प्रांतों के कृषि एवं सहकारिता मंत्री उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को आश्वस्त किया कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मध्यप्रदेश में सुनियोजित प्रयास होंगे। इस दिशा में कृषि, सहकारिता और उद्यानिकी विभाग की गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई हैं। कृषि विभाग की तरफ से राज्यस्तरीय निगरानी समिति और जिलास्तरीय निगरानी समितियों के गठन, कृषक उत्पादक समूह (एफपीओ) को आंदोलन के रूप में विस्तारित करने का लक्ष्य है। हर विकासखंड से योजना के अंतर्गत कम से कम दो प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सहकारिता विभाग की तरफ से भारत सरकार के उपक्रम नाबार्ड, एनसीवीसी के अधिकारियों को शामिल करते हुए सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और मार्कफेड के अधिकारियों की दो कमेटियों का गठन किया गया है। निर्धारित मापदंडों के मुताबिक 263 जिलास्तरीय/ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) और 54 विपणन समितियों को चिन्हित कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में उन्नत सीडग्रेंडिंग प्लांट, वेक्यूम व्हीट पैकिंग यूनिट, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज की श्रृंखला विकसित होगी। मध्यप्रदेश में एक जिला एक पहचान के अंतर्गत विभिन्न जिलों में सब्जियों और फलों के उत्पादन की अधिकता का लाभ लेते हुए प्रोसेसिंग यूनिट विकसित होंगी। वर्तमान में उत्पादन अधिक हो जाने से उत्पाद की कीमत कम हो जाने की स्थिति में किसान लाभान्वित नहीं हो पाता। उद्यानिकी विभाग की ओर से पैकहाउस, कोल्डरूम, इंटेग्रेटेड हाउस, इंटेग्रेटेड कोल्ड चेन सप्लाई, मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉर्टिंग एण्ड ग्रेडिंग के प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं। इस संबंध में हाल ही में आत्मनिर्भर वेबिनार में रोडमैप बनाने के लिए हुए विचार–विमर्श में ठोस सुझाव मिले हैं। इन्हें क्रियान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस मत के वे पक्षधर हैं कि सिर्फ सब्सिडी आदि से किसान कल्याण संभव नहीं है बल्कि दीर्घ अवधि की प्लानिंग तैयार कर बिचौलियों से उत्पादकों को बचाते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के अंतर्गत बेहतर परिणाम लाने के लिए संकल्पबद्ध है।

कृषि क्षेत्र में आएगी क्रांति रू केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि अधोसंरचना कोष में एक लाख करोड़ की राशि के प्रावधान और क्रियान्वयन के बिंदुओं पर राज्यों से हो रही यह बातचीत इस कार्य को गति प्रदान करेगी। कृषि क्षेत्र में वृहद स्तर पर निवेश से निश्चित ही क्रांति आएगी। आमूल–चूल परिवर्तन के यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत में बड़ा योगदान देंगे। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि एक लाख करोड़ के पैकेज को 8 जुलाई को मंजूरी मिली थी, एक माह बाद ही 9 अगस्त को कार्यवाही पूरी की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस दिन साढ़े आठ करोड़ किसान परिवारों को पीएम किसान सामान्य निधि के 17 हजार करोड़ रुपये प्रदान कर लाभान्वित किया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल द्वारा योजना के अनुमोदन के 30 दिन बाद 2282 कृषक सोसायटियों को 1000 करोड़ रुपये से अधिक राशि की मंजूरी दी गई। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना सशक्त करने और किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए राज्य चिंता करें। पैकेज का व्यवस्थित क्रियान्वयन का प्रयास हों। इस संबंध में वेबिनार आयोजित कर भी विचार किया जाए। कृषक उत्पादक समूह (एफपीओ) के लिए प्रावधान से तस्वीर बदलेगी छोटे और मझोले किसानों की संख्या 85 प्रतिशत है। ऐसे किसानों का रकबा बढ़े और उत्पादन में लगने वाली सामग्री कम हो और लागत में भी कमी आए इसके अलावा सिंचाई के लिए पानी, उर्वरक आदि का संतुलित उपयोग हो। वैश्विक मापदंड से कृषि कार्य के प्रयास हों। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि बैंकों से हुए अनुबंध का लाभ भी किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में प्राप्त होगा।

कृषि सचिव का प्रजेंटेशन

प्रारंभ में भारत सरकार के कृषि सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत केन्द्र द्वारा पोषित कृषि अधोसंरचना कोष के वित्तीय प्रावधान, ब्याज पर अनुदान, क्रेडिट गारंटी, हितग्राही और संस्था की पात्रता, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए संचालित होने वाली परियोजनाओं, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन परियोजनाओं, सेक्टर विशेष को फोकस कर उद्यामियों को दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में राज्य भी नवाचार कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार हो रहे ड्राफ्ट का क्रियान्वयन कृषि अधोसंरचना कोष से संबद्ध कर प्राप्त किया जा सकता है। विश्व बैंक या अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्ति के प्रयास किए जा सकते हैं। इसी वित्तीय वर्ष में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बना लेने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

अनुकूल परितंत्र के निर्माण की पहल

किसानों को उद्यमी बनाने की दिशा में भारत सरकार ने एक अनुकूल परितंत्र के निर्माण की पहल की है। यह पहल देश के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचने में सक्षम है। मध्यप्रदेश के लिए कृषि अधोसंरचना कोष में 7 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है। योजना में शासकीय सहायता के प्रावधान किसानों के लिए किए गए हैं। इसमें अधिकतम दो करोड़ रुपये की ऋण राशि के प्रकरण में वार्षिक ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट रहेगी। यह छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। क्रेडिट गारंटी के अंतर्गत अधिकतम 2 करोड़ की ऋण राशि पर प्रति प्रकरण क्रेडिट गारंटी शुल्क आवश्यक राशि का भुगतान सरकार करेगी। योजना में प्राथमिक कृषि साख समितियों, किसान उत्पादक समूहों, स्वसहायता समूहों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के साथ ही केन्द्रीय/राज्य एजेंसियां या सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजना को पात्र माना गया है। सम्मिलित प्रयासों से भारत को विश्व की फूड मार्केट बनाने का प्रयास है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अध्यक्ष श्री गोविंदा राजुलु चिंताला ने अपने संबोधन में कृषि अधोसंरचना कोष को सराहनीय कदम बताया। वीडियो कान्फ्रेंस में मध्यप्रदेश के विभिन्न मंत्री, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े उपस्थित थे।

मछली पालन से युवाओं को जोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध करवायें जाए

भोपाल। जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने और मत्स्य व्यवसाय से युवाओं को जोड़ने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने मछुआ सहकारी समितियों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और मछली पालन से रोजगार के नये साधन विकसित करने के निर्देश भी दिये।

मत्स्य विकास मंत्री श्री सिलावट ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि मछली पालन से होने वाली आय कृषि आय से अधिक होती है। अतरू मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा किये जाये। विभाग समितियाँ बनाकर नई कार्ययोजना बनाये और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़े। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री अश्विन राय, मुख्य प्रबंधक श्री पुरूषोत्तम धीमान, संचालक श्री सक्सेना और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।